राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष – 04 | अंक – 09 | जौनपुर | शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

दिल्ली उच्च न्यायालय ने संजय भंडारी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ब्रिटेन स्थित हथियार सलाहकार संजय भंडारी द्वारा दायर एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस याचिका में, उन्हें ष्भगोड़ा आर्थिक अपराधीष घोषित करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, भंडारी ने यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने भंडारी और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दलीलें सुनीं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। निचली अदालत के 5 जुलाई के आदेश का बचाव करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीठ को बताया कि निचली अदालत ने एक मूल्यांकन आदेश की पूरी जानकारी होने के बावजूद अपना फैसला सुनाया था, जिसमें खुलासा हुआ था कि 655 करोड़ रुपये की संपत्ति ष्गुप्त रूप से अर्जितष की गई थी। एजेंसी ने कहा कि इस तरह के निष्कर्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत भंडारी को भगोड़ा अपराधी घोषित करने को उचित ठहराते हैं। ईडी के रुख का विरोध करते हुए, भंडारी के वकील ने तर्क दिया कि मूल्यांकन कार्यवाही पूरी होने से पहले ही अभियोजन शुरू कर दिया गया था। ष्अगर आकलन पूरा नहीं था, तो यह मानने का क्या कारण था कि कर चोरी 100 करोड़ रुपये से ज्यादा थी,ष उनके वकील ने दलील दी और कहा कि निचली अदालत का फैसला समय से पहले लिया गया था। इस घोषणा को पलटने की मांग करते हुए, उनके वकील ने चेतावनी दी कि भंडारी के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। अदालत को बताया गया, ष्जैसे ही उन्हें भगोड़ा घोषित किया जाएगा, उनके पास कोई उपाय नहीं बचेगा।ष ईडी की याचिका पर 5 जुलाई को पारित आदेश ने एजेंसी के लिए भंडारी की सभी संपत्तियाँ, जिनकी कीमत कई सौ करोड़ रुपये है, जब्त करने का रास्ता साफ कर दिया था। यह घटनाक्रम ब्रिटेन की एक अदालत द्वारा उनके प्रत्यर्पण के खिलाफ फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद आया, जिससे उनकी भारत वापसी की संभावना कम हो गई। भंडारी के वकीलों ने जोर देकर कहा कि ईडी का तरीका कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है।

गौरव पथ... स्मार्ट क्लास रूम व ईवी स्टेशन के साथ बढ़ेंगी डिजिटल सेवाएं : योगी आदित्यनाथ

लखनऊ , (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग की समीक्षा की। उन्होंने जिला मुख्यालयों स्थित नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित बनाने की योजना के क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया। कहा कि स्मार्ट–विकसित नगर पालिका योजना का उद्देश्य पालिकाओं को आधुनिक, आत्मनिर्भर और नागरिक–केंद्रित रूप में विकसित करना है। इस योजना तहत नगर पालिकाओं में गौरव पथ, पिंक टॉयलेट, शहरी सुविधा केंद्र, स्मार्ट क्लास रूम व आंगनबाड़ी, थीम आधारित पार्क, ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण, जलाशयों का पुनर्जीवन, ईवी चार्जिंग स्टेशन, ग्रीन क्रेमेटोरियम और डिजिटल सेवाओं जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए उत्सव भवन, सामुदायिक केंद्र और श्वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्टश आधारित ढांचे भी स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस योजना को हब–एंड–स्पोक मॉडल पर लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लखनऊ और गोरखपुर स्थित एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से समीपवर्ती जिलों की नगर पालिकाओं को जोड़ा जा सकता है। इससे सुरक्षा, निगरानी और शिकायत निवारण जैसी सेवाओं में आधुनिकता आएगी। साथ ही संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। अधिकारियों ने बताया कि नगर निकायों को चार करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान देने का प्रस्ताव है। यह उनकी जनसंख्या और कार्य दक्षता पर आधारित होगा। बैठक में लखनऊ और कानपुर में 200 इलेक्ट्रिक बसों को नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट है।

यूएन मिशन में महिलाओं की भागीदारी का भारत प्रबल समर्थक : राजनाथ सिंह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र की महिला सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में राजनाथ सिंह ने यूएन मिशन में में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की। रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि भारत, संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिलाओं की भागीदारी का प्रबल समर्थक है। संयुक्त राष्ट्र की महिला सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, श्आज यहां संयुक्त राष्ट्र के 15 देशों की सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति संयुक्त राष्ट्र की एकता और सहयोग की उसकी भावना को दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र ने शांति अभियानों में महिला अधिकारियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। महिला अधिकारी शांति अभियानों में बहुमूल्य दृष्टिकोण लाती हैं। वे अक्सर स्थानीय समुदायों के साथ गहरा विश्वास बढ़ाने में सक्षम होती हैं और उनकी उपस्थिति यौन हिंसा को रोकने, मानवीय सहायता तक पहुंच में सुधार और लैंगिक समानता को बढ़ाने में मददगार साबित हुई है। महिला शांति सैनिक रोल मॉडल के रूप में काम करती हैं, स्थानीय महिलाओं और लड़कियों को प्रेरित करती हैं राजनाथ सिंह ने कहा कि श्संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता होने के नाते, भारत महिलाओं की भागीदारी और मिशनों में एकीकरण का प्रबल समर्थक रहा है। हमारी विरासत 1960 के दशक में कांगो में महिला चिकित्सा अधिकारियों के साथ शुरू हुई, और आज भी हम लैंगिक असमानताओं को पाटने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। हम महिला अधिकारियों को शांति अभियानों के लिए तैयार करते हैं, ।

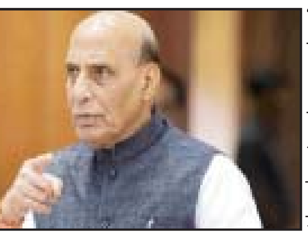

भारत के शिखर पर पहुंचने तक किसी को आराम का अधिकार नहीं : अमित शाह

तिरुवनंतपुरम, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है और उन्होंने देश के लोगों से आह्वान किया कि वे देश को दुनिया के हर क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। हालांकि, उन्होंने इस बात पर निराशा भी जाहिर की कि केरल आज भी वहीं है जहां वह 11 साल पहले था, और उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा के कारण पैदा हुए ठहराव को राज्य को पीछे धकेलने के लिए जिम्मेदार ठहराया। केरल में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा श्भारत लंबे समय तक आर्थिक अस्थिरता का शिकार रहा। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी। कांग्रेस सरकार अपने 10

वर्षों में केवल एक ही अच्छी बात कर पाई कि उन्होंने इसे 12वें स्थान पर नहीं जाने दिया। पिछले 11 वर्षों में, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 11वें स्थान से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। शाह ने कहा, जब तक हम शिखर पर नहीं पहुंच जाते और एक महान भारत का निर्माण नहीं कर लेते, तब तक किसी को भी आराम करने का अधिकार नहीं है। जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने एक लक्ष्य रखा था कि आजादी के 75 से 100 वर्ष की इस यात्रा में, सभी 1.4 अरब नागरिक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और देश को दुनिया के हर क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचाएं। शाह ने आगे कहा कि शांति और विकास की दृष्टि से, जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा तब प्रधानमंत्री मोदी के 11 वर्षों के शासन को स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा।

भाजपा का सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा होगा भ्रष्टाचार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के गयाजी में साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई और घुसपैठ का मामला भाजपा–जदयू का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। केंद्र सरकार ने संसद में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों के जेल जाने पर उनको पद से हटाने का कानून लाने का प्रस्ताव किया है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। पीएम ने विपक्ष के इस विरोध को भी जमकर भुनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि राजद–कांग्रेस इस कानून का विरोध केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने जेल जाने का डर है। मोदी ने बार–बार लोगों को लालटेन युग में बिहार में दुर्दशा होने की बात कही। उन्होंने कहा कि

लालटेन युग में बिहार की धरती लाल हो जाती थी। यह कहकर वे राजद के उसी दौर को याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे, जब बिहार में संगठित अपराध अपने चरम पर था। नई पीढ़ी के बहुत से मतदाताओं को वह दौर याद नहीं होगा। लेकिन पीएम ने अपने भाषणों से लोगों को उसी दौर की याद दिलानी चाही। इससे साफ है कि वे अभी भी कथित जंगलराज को अपनी राजनीतिक ताकत बनाकर रखना चाहते हैं। भाजपा बिहार विधानसभा चुनावों में इसका लाभ लेने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री ने जिस तरह बिना किसी भ्रष्टाचार के लोगों को नौकरी दिए जाने का मामला उठाया, उससे भी वे राजद कार्यकाल में नौकरी के बदले भूमि लिए जाने के मामले की याद दिला रहे थे। इसके जरिए भी लोगों को यही बताने की कोशिश की गई कि राजद कार्यकाल में किस तरह भ्रष्टाचार होता था।

वोट चोरी को घुसपैठ से जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसी समय बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। वे लोगों को याद दिला रहे हैं कि जनता के वोट का अधिकार छीना जा रहा है। राहुल गांधी खुलकर इसके लिए श्वोट चोरीश शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब मोदी ने इसे श्घुसपैठश के मुद्दे से जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि घुसपैठियोंके कारण बिहार के साथ–साथ देश की सुरक्षा के सामने बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।

शिक्षक समेत दो सरकारी कर्मचारी निकले लश्कर–ए–तैयबा के मददगार : मनोज सिन्हा

श्रीनगर, (एजेंसी)। जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में दो सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ब) के तहत की गई है, जो राज्य को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बिना जांच के कर्मचारी को बर्खास्त करने का अधिकार देता है। जांच एजेंसियों के अनुसार, दोनों कर्मचारी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर–ए–तैयबा के लिए काम कर रहे थे। कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों ने इनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए हैं, जिनमें आतंकियों को सहायता पहुंचाने, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और देशविरोधी तत्वों के साथ संपर्क होने जैसी गंभीर बातें सामने आई हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वह आतंकवाद और उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। ऐसे मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

सिद्धारमैया ने विधानसभा में भाजपा शासित राज्यों की 20 भगदड़ की घटनाओं का किया जिक्र

बंगलूरू, (एजेंसी)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को भाजपा शासित राज्यों में हुई 20 भगदड़ों का जिक्र किया। उन्होंने ऐसी घटनाओं के लिए सामूहिक उन्माद को जिम्मेदार ठहराया। यह बात उन्होंने 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ पर चर्चा के दौरान कही, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। सदन में मुख्यमंत्री ने भगदड़ की एक सूची पढ़ी, जिसमें 3 अगस्त, 2008 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के नैना देवी मंदिर में हुई भगदड़ शामिल थी, जब प्रेम सिंह धूमल मुख्यमंत्री थे। इसके बाद 2008 में जोधपुर में हुई भगदड़ का जिक्र आया, जिसमें 250 लोग मारे गए थे। उन्होंने जिन भगदड़ों का जिक्र किया, उनमें 2013 में रतनगढ़, 2021 में हरिद्वार, 2023 में मध्य प्रदेश के सीहोर और 2024 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ शामिल है, जिसमें 121 लोग मारे गए थे। उन्होंने इस साल जनवरी में कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में हुई भगदड़ का भी जिक्र किया, जिसमें 39 लोगों की जान चली गई थी। मुख्यमंत्री ने 2022 में गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे का भी जिक्र किया, जिसमें 135 लोग मारे गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा, श्मेरे 42 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। मैंने कभी भगदड़ में 11 लोगों को मरते नहीं देखा। मुझे बहुत दुख हुआ है। मैंने उसी दिन अपना दुख व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि लोगों ने आईपीएल मैच में आरसीबी की जीत को बंगलूरू का गौरव माना। इससे पैदा हुआ जन उन्माद ही भगदड़

के पीछे था। सिद्धारमैया ने कहा, श्लोकतंत्र में हमें कभी–कभी लोगों की उम्मीदों के आगे झुकना पड़ता है। यही लोकतंत्र की निशानी है।श उन्होंने बताया कि उन्हें आरसीबी के विजय समारोह में शामिल होना था।

भगदड़ मामले पर जी परमेश्वर ने विधानसभा में रखी अपनी बात

इससे पहले, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने विधानसभा में बंगलूरू भगदड़ पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी। हमने पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया और सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जॉन माइकल डीश्कुन्हा से भगदड़ पर रिपोर्ट मंगवाई। उन्होंने कहा कि हम भगदड़ में गई जानों को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम भीड़ प्रबंधन विधेयक लेकर आए हैं।

चिन्नास्वामी स्टेडियम में 33000 लोगों के बैठने की क्षमता

गृह मंत्री ने कहा कि भीड़–भाड़ वाली जगहों पर उपलब्ध सुविधाओं को तय करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया की आवश्यकता है। इसके अनुसार, एक मसौदा तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम देश के सर्वश्रेष्ठ स्टेडियमों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह बारिश के पानी को तुरंत सोख लेता है, लेकिन इसकी क्षमता केवल 33,000 लोगों के बैठने की है।

जी परमेश्वर बोले– हमें एक लाख से ज्यादा क्षमता वाले स्टेडियम की जरूरत

मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम देश के खूबसूरत स्टेडियमों में से एक है,

आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर रामनाथ कोविंद होंगे मुख्य अतिथि, नागपुर में होगा सबसे बड़ा आयोजन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस साल 2025 में अपना जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा है। जन्म शताब्दी वर्ष पर होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला विजयादशमी (2 अक्तूबर) पर नागपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के साथ होगी। इस सबसे प्रमुख कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस अवसर पर स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। आरएसएस ने शताब्दी वर्ष में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। इसमें मोहन भागवत के द्वारा दिल्ली सहित देश के चार प्रमुख शहरों (मुंबई, कोलकाता और चेन्नई) में मुख्य कार्यक्रमों में लोगों को संबोधित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में संबंधित क्षेत्रों की विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां

मौजूद होंगी। मोहन भागवत इन कार्यक्रमों में लोगों को संघ की अब तक की उपलब्धियां और भविष्य में अपनी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इससे संघ के विषय में लोगों की धारणा स्पष्ट हो सकेगी। संघ ने समाज से जातिवाद दूर करने और कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को अपने परिवार और समाज से जुड़ने को अपना प्रमुख लक्ष्य बनाया है। शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों में संघ के कार्यकर्ता सेवा बस्तियों में जाकर उनसे संपर्क करेंगे और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास करेंगे। हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आनुषंगिक संगठनों के सहयोगियों के साथ मिलकर दुनिया की नई परिस्थितियों पर विचार किया है। इसमें भारत को आर्थिक तौर पर समृद्ध करने के उपायों पर चर्चा की गई है। अमेरिका, चीन, रूस और यूक्रेन जैसे देशों के आंतरिक संबंधों का भारत पर पड़ रहे असर और उससे निपटने की नीति पर भी विचार किया गया है।

संसद की सुरक्षा में सेंध, दीवार कूदकर परिसर में घुसा शख्स सुरक्षा बलों ने पकड़ा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संसद भवन की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक हुई है। एक व्यक्ति पेड़ के सहारे दीवार कूद कर सुबह लगभग 5.50 बजे संसद भवन में घुस गया। रेलभवन की तरफ से दीवार कूदकर नई संसद भवन के गरुड़ द्वार तक पहुंच गया था। संसद भवन में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। नई दिल्ली, पुलिस उपायुक्त, देवेश महला ने बताया कि पकड़े गए युवक की पहचान रामा के रूप में हुई है और वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। शुक्रवार सुबह करीब 5.50 बजे उसने संसद भवन की

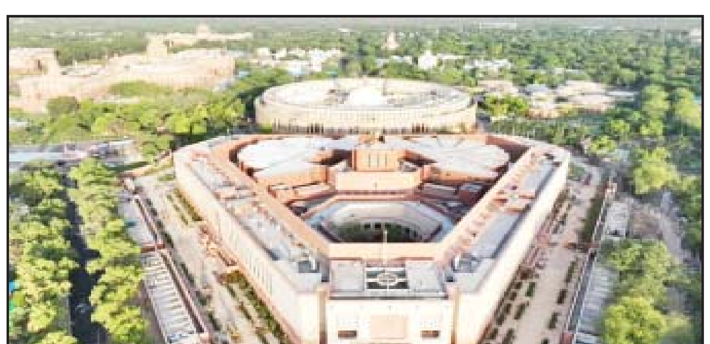

चहारदीवारी फांदने का प्रयास किया, लेकिन सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत होता है और आगे की पूछताछ और सत्यापन प्रक्रिया जारी है। अगस्त 2024 में भी देश की नई संसद भवन की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। रेड क्रॉस रोड की तरफ से एक युवक दीवार फांद कर संसद भवन के परिसर में कूद गया था। हालांकि, संसद भवन में घुसने से पहले ही सुरक्षा में तैनात जवानों ने उसे पकड़ लिया था। शुरुआती जांच के बाद इम्तियाज अली नामक युवक को मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा था। दिल्ली पुलिस व खुफिया विभाग समेत देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों ने युवक से संयुक्त रूप से पूछताछ की थी। संसद की सुरक्षा में चूक के इस मामले के बाद दिल्ली पुलिस समेत देश की सुरक्षा एजेंसियों में अफरा–तफरी मच गई थी।

दिसंबर 2023 में भी सुरक्षा में चूक का सामने आया था मामला

दिसंबर 2023 में भी संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली थी। सुरक्षा घेरा तोड़कर लोकसभा में विजिटर गैलरी से दो संदिग्ध कूद पड़े थे। संसद की कार्यवाही के दौरान दोनों शख्स बेंच पर चढ़कर कूदने लगे।

संपादकीय

मनी गेमिंग पर रोक

यह एक हकीकत है कि ऑन लाइन मनी गेमिंग यदि लत बन जाए तो यह संपन्न व्यक्ति को भी बदहाल कर सकती है। एक आंकड़े के अनुसार देश में हर साल 45 करोड़ लोग बीस हजार करोड़ गवां देते हैं। सब कुछ गंवा कर आत्महत्या करने के मामले भी प्रकाश में आते हैं। सवाल इन लालच जगाने वाली मनी गेमिंग की पारदर्शिता को लेकर भी उठते रहे हैं। इन्हीं चिंताओं के बाद सरकार ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 लेकर आई है। जिसे अब गंभीर चर्चा के बिना संसद ने पारित भी कर दिया है। यह विधेयक पैसे से खेले जाने वाले किसी भी ऑनलाइन गेम को गैरकानूनी घोषित करता है। दरअसल, सरकार का मानना है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग एक सामाजिक और जन स्वास्थ्य के लिये घातक समस्या है। सरकार के मुताबिक, वह ई–स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने के लिये उत्सुक है, जिसमें कोई वित्तीय जोखिम न हो। निर्विवाद रूप से हाल के वर्षों में ऑनलाइन स्किल गेमिंग उद्योग ने तेजी से विस्तार किया है। जिसमें पूर्व और वर्तमान क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों के प्रचार की भी भूमिका रही है। यहां उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन गेमिंग का वार्षिक राजस्व 31,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके साथ ही यह हर साल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में बीस हजार करोड़ रुपये से अधिक का योगदान देता है। लेकिन इसके साथ चिंता का विषय यह भी है कि सुनहरे सब्जबाग दिखाने वाले कई ऑनलाइन गेमिंग एप लत, खेलने वाले आम लोगों के आर्थिक नुकसान और मनी लॉन्ड्रिंग को भी बढ़ावा देते हैं। यही वजह है कि ऑनलाइन गेमिंग में अपनी जमा पूंजी लुटाने वाले बदकिस्मत उपयोगकर्ता नाकामी के बाद आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। निस्संदेह सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर एक बड़ा जोखिम भी उठाया है। इसमें सरकार को राजस्व की भारी हानि भी हो सकती है। वहीं तसवीर का दूसरा पक्ष यह भी है कि कई उद्यमी तेजी से उभरते इस गेमिंग व्यवसाय के पराभव की चिंता जता रहे हैं। बताया जाता है कि देश में जो ग्यारह सौ से अधिक गेमिंग कंपनियां तथा करीब चार सौ स्टार्टअप ऑनलाइन गेमिंग उद्योग से जुड़े हैं, जिनके नियमन के बारे में सोचा जा सकता था। उनकी चिंता है कि इससे बड़ी संख्या में नौकरियां जा सकती हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि उसने जनकल्याण को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है। लेकिन दूसरी ओर चिंता जतायी जा रही है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के वैध प्लेटफॉर्म बंद होने से खेलने वाले लोग अनियमित विदेशी ऑपरेटरों के शिकार बन सकते हैं। इंटरनेट का विस्तृत दायरा और विदेशी ऑनलाइन ऑपरेटर विधेयक के प्रमुख उद्देश्यों को विफल करने की कोशिश कर सकते हैं। निस्संदेह, वित्तीय प्रणालियों की अखंडता के साथ–साथ राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए। माना जा रहा है कि इस नये कानून को बनाने की जरूरत संभवतरू छह हजार करोड़ रुपये वाले महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले के बाद महसूस की गई। जिसकी जांच सीबीआई और ईडी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ शीर्ष राजनेताओं और नौकरशाहों पर सट्टेबाजी एप के यूएई स्थित प्रमोटरों के साथ संबंध होने के आरोप लगे हैं। जो कथित तौर पर हवाला कारोबार और विदेशों में धन–शोधन के कार्यों में लिप्त बताये जाते हैं।

बदलाव के बीज से ही लहलहाएंगी फसलें

राजेश

हमारे राजनेता और नीति–निर्माता क्यों नहीं चीन से यह बात सीखते कि कैसे उसने 12 करोड़ हेक्टेयर उपजाऊ जमीन पर एक श्लाल रेखाश खींच दी है, क्योंकि भविष्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के वास्ते इतनी जमीन संरक्षित करना एक आवश्यकता है। कुछ साल पहले, 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' नामक संगठन के स्थापना–वर्षों के दौरान, कि एक वक्त यह गांव सबसे अधिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वाला रहा। जीडीपी से भी ज्यादा यह जानना महत्वपूर्ण है कि इसने गरीबी और अभाव से जुड़े तमाम प्रतीकों जैसे कि बढ़ती शराबखोरी, बीमारियों का प्रसार, शिक्षा की कमी को सफलतापूर्वक रोक दिया। नतीजतन गांव में विपरीत–पलायन होने लगा। जब किसी गांव में आर्थिक बदलाव आता है, तो जो लोग पेट की खातिर गांव छोड़कर जाने को मजबूर हुए,

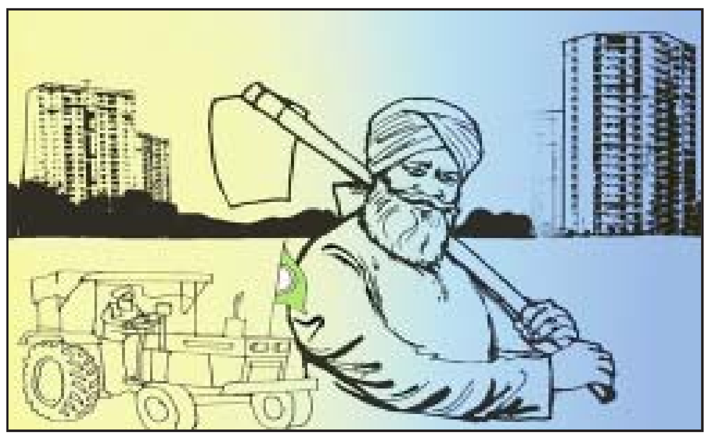

अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि मैं उनके करीबी विश्वासपात्र मनीष सिसोदिया द्वारा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक गुमनाम से गांव हिवारे बाजार पर बनाई गई एक दस्तावेजी फिल्म देखूं, जो अपने चमत्कारिक कायाकल्प के कारण अचानक से खबरों में छाई थी। सिसोदिया की इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे एक बारहों माह सूखाग्रस्त एवं अभावग्रस्त गांव ने ग्राम सभा में सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया पर अमल करते हुए, स्वशासन के जरिए खुद को एक जीवंत आदर्श गांव में बदल डाला। इस गांव में वयस्कों की औसत वार्षिक आय जहां वर्ष 1989 में महज 8,000 रुपये थी वह 2012–13 की शुरुआत में बढ़कर 28,000 रुपये हो गई। मुख्य रूप से, जनभागीदारी आधारित सर्वांगीण विकास के इस उल्लेखनीय मॉडल ने अंततः गांव में 54 करोड़पति पैदा कर दिए। कोई हैरानी नहीं वे वापस लौटना चाहते हैं। कोई नौ साल पहले, मुझे सुखद आश्चर्य हुआ जब केजरीवाल ने शहिवारे बाजार की कहानी, अरविंद केजरीवाल की जुबानीश, नामक शीर्षक वाली अन्य यूट्यूब वीडियो की कहानी बड़ी वाक्पटुता से मुझे सुनाई थी। वह चाहते थे कि गांव के अद्भुत सरपंच पोपट लाल के नेतृत्व में जिस सामाजिक–आर्थिक सोच ने रास्ता दिखाया, उसका अनुसरण देश भर के सभी 7 लाख गांवों में किया जाए। बस उन्हें सुनिए और आपको अहसास होगा कि कैसे केजरीवाल ने ग्रामीण समृद्धि लाने की एक 'पारसमणि' खोज ली थी। दरअसल, वीडियो में वे एक नया पंजाब बनाने की बात भी करते हैं और कहते हैं कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो इस कृषि प्रधान सूबे में हिवारे बाजार की सफलता गाथा को लागू किया जाएगा। लेकिन, हमेशा की तरह, सरकार बनने के बाद, यह भी एक भूली–बिसरी कहानी बनकर रह गई। पार्टी को मिले भारी चुनावी जनादेश को देखते हुए, यह अवसर निश्चित रूप से मौजूद था। कुल 117 सीटों में आम आदमी पार्टी को 92 पर मिली जीत के साथ, उसके पास हिवारे बाजार के अनूठे विकास मॉडल को अपनाकर भविष्य की राह फिर से गढ़ने के लिए पर्याप्त अनुकूल परिस्थितियां थीं, जिससे आखिरकार एक नए पंजाब के उदय की रूपरेखा को प्रदर्शित किया जा सकता था। एक कृषि प्रधान राज्य होने के नाते, बिखरती कृषि–आर्थिकी से स्थाई रूप से पार पाने के लिए जरूरी तमाम अवयव पंजाब के पास मौजूद हैं, न केवल जलवायु–अनुकूल है बल्कि आर्थिक–पर्यावरणीय रूप से व्यवहार्य और समृद्ध एक अद्भुत ग्रामीण क्षेत्र के तौर पर भी। अगर एक सूखाग्रस्त गांव 54 करोड़पति पैदा करने पर गर्व कर सकता है, तो कल्पना कीजिए कि पंजाब के 12,000 से ज्यादा गांव, जहां पहले से ही 98 प्रतिशत खेत सिंचाई युक्त है, वहां कितनी बड़ी संख्या में करोड़पति आसानी से पैदा हो सकते हैं। अगर पानी को गांवों के विकास की धुरी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो निश्चित रूप पंजाब से बहुत आगे है। आवश्यक रूप से इसके लिए एक नई एवं कल्पनाशील सोच की आवश्यकता है, जिसका मास्टर प्लान पहले से ही मौजूद है। लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको ठंडे बस्ते में डालकर, आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट रूप से इस महान अवसर को गंवा दिया है। और अब सिसोदिया द्वारा अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को दी गई यह नवीनतम सलाह रू '2027 का चुनाव जितवाने के लिए, साम, दाम, दंड, भेद, सच, झूठ, सवाल, जवाब, लड़ाई, झगड़ा जो करना पड़ेगा... तैयार हैं जोश के साथ?', सब कुछ उजागर कर जाती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि लैंड पूलिंग योजना अकारण नहीं थी। मेरी हताशा राजनीतिक नेतृत्व की उस कथनी पर यकीन न कर पाने से भी है, जिसे वे बार–बार हमें बताते रहते हैं। शुरुआत करने के लिए, निश्चित रूप से पंजाब को फसल विविधीकरण की जरूरत है, जो प्रचलित गेहूं–धान फसल चक्र पद्धति की जगह ले सके, लेकिन लैंड पूलिंग वह विविधीकरण नहीं था जिसकी आस पंजाब को है। मेरी समझ में लैंड पूलिंग योजना वास्तव में नीति निर्माताओं में व्याप्त 'बौद्धिक सूखे' का अक्स है और इसमें सेवारत के अलावा प्रभावशाली सेवानिवृत्त नौकरशाही, दोनों, शामिल हैं। कुछ महीने पहले पंजाब विश्वविद्यालय में आयोजित एक नीति संवाद में, सेवानिवृत्त नौकरशाहों को खेती की एवज में तेज औद्योगीकरण की वकालत करते सुनना कोई हैरानी की बात नहीं थी। यह सिर्फ पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी नहींय देशभर में हर किस्म के राजनीतिक दल जमीनें हड़पने में लगे हैं। किसी भी प्रमुख दल का नाम लीजिए, उसकी नजर जमीन हड़पने पर ही है। हरियाणा आगामी 6 नए इंटिग्रेटेड मल्टीमॉडल टाउनशिप के लिए 35,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की योजना बना रहा है। कर्नाटक में, साढ़े तीन साल तक चले किसानों के लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद, मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु के आसपास के 13 गांवों तक फैले देवनहल्ली तालुका में 1,777 एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण करने वाला फैसला वापस ले लिया है। इत्यादि।

इसे कुछ भी नाम दें, 164 गांवों में लगभग 65,553 एकड़ भूमि का अधिग्रहण उस तरह का विविधीकरण नहीं था जिसकी पंजाब को जरूरत थी। यह जमीन हड़पने की योजना के अलावा कुछ नहीं थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चार हफ्तों के लिए लैंड पूलिंग नीति पर रोक लगाने के तुरंत बाद, किसान समूहों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई, जिसमें ट्रैक्टर रैलियां और कई गांवों में आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए श्प्रवेश निषेधश नोटिस बोर्ड और बैनर लगना शामिल थे, इसके चलते पंजाब सरकार द्वारा घातक नीति को वापस लेने का फैसला राहत की सांस के रूप में आया, जिसकी बहुत जरूरत थी। सनद रहे, न्यायालय ने यह भी कहा था कि अधिगृहीत की जा रही भूमि अत्यंत उपजाऊ है और द्विफसलीय है, जिसका अर्थ है कि केवल असाधारण मामलों में ही इसका अधिग्रहण हो सकता है, और इस तरह यह नीति भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के विरुद्ध जाती है। इतना ही नहीं, भारत–माला राजमार्ग परियोजना के तहत जमीन के अधिग्रहण से, जिसमें हर 10 किलोमीटर पर फूड कोर्ट बनने हैं, उपजाऊ जमीन तेजी से हड़पी जा रही है। और यह मुझे आश्चर्यचकित करता है। हमारे राजनेता और नीति–निर्माता क्यों नहीं चीन से यह बात सीखते कि कैसे उसने 12 करोड़ हेक्टेयर उपजाऊ जमीन पर एक श्लाल रेखाश खींच दी है, क्योंकि भविष्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के वास्ते इतनी जमीन संरक्षित करना एक आवश्यकता है। भारत में दूरदर्शी नेताओं की ऐसी फसल कब होगी जो पंजाब को उस भूमिका के लिए बचाकर रख सके, जिसे फिर से निभाने को कहने की नौबत भविष्य में बनने वाली है–जलवायु अनिश्चितताओं के वक्त एक भूखे राष्ट्र को फिर से भोजन उपलब्ध कराना। सत्ता में किसी भी तरह बने रहने के लिए साम, दाम, दंड, भेद जैसे हथकंडे लागू करने की बजाय पंजाब को भगवंत मान सरकार से उम्मीद थी कि वह अपने गांवों में बदलाव के बीज बोते, जिससे हजारों फूल खिलते। निश्चित तौर पर पंजाब को एक ऐसी नीतिगत रूपरेखा की जरूरत है जो एक क्षीण होती कृषि सभ्यता को लगभग पतन से बचा सके। न कि वह जो इसकी बहुमूल्य जमीनी संपदा को बेचने पर आमादा हो।

न्याय के मार्ग में बाधक न बन पाए बेंच हंटिंग

न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कई ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। अदालतों में मामलों के आवंटन के लिए पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत और रैंडम प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम हो और पक्षपात की संभावना नगण्य हो जाए। कानूनी दुनिया में 'बेंच हंटिंग' शब्द इन दिनों सुर्खियों में है, खासकर 16 वकीलों को बार काउंसिल द्वारा मिले नोटिस के बाद। यह केवल एक कानूनी शब्दावली नहीं, बल्कि हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता पर एक चिंता पैदा करती है। यह न्याय को प्रभावित करने और अपनी सुविधानुसार परिणाम प्राप्त करने का एक सीधा प्रयास है, जो न्यायिक नैतिकता के खिलाफ है। बेंच हंटिंग न केवल न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को खतरे में डालती है, बल्कि आम जनता के न्याय प्रणाली में विश्वास को भी गहरी चोट पहुंचाती है। यह प्रथा न्याय के मार्ग को बाधित करती है। सरल शब्दों में, बेंच हंटिंग का मतलब है किसी खास मामले की सुनवाई के लिए अपनी पसंद के जज या पीठ (बेंच) की तलाश करना। वकील या उनके मुवक्किल ऐसे जज के सामने अपना मामला ले जाने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे उनके पक्ष में फैसला दे सकते हैं, या ऐसे जज से बचने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे उनके खिलाफ जा सकते हैं। यह अक्सर कानूनी दांव–पेंच का हिस्सा बन जाता है, जहां मामले को सूचीबद्ध कराने के लिए अलग–अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि बार–बार मामले को वापस लेना और फिर से दायर करना, या फिर मामले को इस तरह से प्रस्तुत करना कि वह एक विशिष्ट बेंच के सामने आ जाए।

.... विविध ....

लालबागचा राजा : सांस्कृतिक धरोहर और भक्तिभाव की मिसाल

चूंकि वह समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समय था और सार्वजनिक गणेशोत्सव भी एक किस्म से अंग्रेजों के विरुद्ध जंग ही थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सभी समुदाय के लोगों को इस सांस्कृतिक गोलबंदी के जरिये अंग्रेजों के विरुद्ध एकत्र किया था। मुंबई में गणेशोत्सव का पर्याय होता है, यहां के लालबाग का गणेश पंडाल। लालबागचा के राजा नाम से मशहूर मुंबई के इस गणेश पंडाल की चर्चा गणेशोत्सव के दौरान पूरी दुनिया में होती है। सनद् 1934 में मुंबई का यह इलाका कोली समुदाय के मछुआरों और छोटे व्यापारियों का इलाका था। आज भी बड़ी संख्या में ये लोग यहां पर हैं, तब समुदाय के कुछ लोगों ने गणेशोत्सव के दौरान व्रत लेने का निर्णय लिया और इलाके में गणेश प्रतिमा स्थापित करने के लिए पंडाल बनाया। कहते हैं इन व्रत लेने वाले भक्तों ने अपने मन में मन्नत मानी थी कि यदि उन्हें इस इलाके में स्थायी बाजार मिल गया तो वे हर साल भगवान गणेश का यहां पंडाल लगाया करेंगे। यह उस समय की बात है जब पेरू चौक का बाजार बंद हो गया था। इस तरह भक्तों की मन्नत पूरी हुई, उन्हें लालबाग बाजार के लिए स्थान मिला। आभार स्वरूप 12 सितंबर, 1934 को यहां पहले सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की स्थापना हुई और तब से लेकर आज तक मुंबई में लालबाग के राजा का पंडाल इसी जगह पर लगता है। चूंकि वह समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समय था और सार्वजनिक गणेशोत्सव भी एक किस्म से अंग्रेजों के विरुद्ध जंग ही थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सभी समुदाय के लोगों को इस सांस्कृतिक गोलबंदी के जरिये अंग्रेजों के विरुद्ध एकत्र किया था। पहला आधुनिक गणेशोत्सव 1893 में पुणे में स्थापित हुआ था। हालांकि इसकी शुरुआत 1890 से ही हो गई थी। वास्तव में लालबाग के राजा का गणेश पंडाल पुणे के गणेश पंडाल की तर्ज पर ही शुरू हुआ था। लालबागचा राजा के नाम से मशहूर यह पंडाल तब से आज तक उस परंपरा को पूरी धज के साथ संभाले हुए है। लालबागचा राजा की मुंबई और देश के लोगों में इतनी श्रद्धा इसलिए है, क्योंकि माना जाता है जो भी सच्चे मन से लालबाग के राजा का दर्शन करके मन्नत मांगता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए भक्त लोग श्रद्धा से इसे नवसाचा गणपति कहते हैं यानी वांछित इच्छा पूरी करने वाले भगवान गणेश। लालबाग के भगवान गणेश की इतनी मान्यता है कि एक से एक वीआईपी भक्त गणपति के दर्शन करने के लिए चार–चार घंटे चुपचाप लाइन में लगे रहते हैं। इस गणेश मंडल की व्यवस्था का औपचारिक रुप से दायित्व कांबली परिवार पर है। वर्ष 1935 से ही रतनाकर कांबली से शुरू होकर उनके पुत्र, उनके पुत्रों के पुत्र इस पारिवारिक परंपरा को संभाले हुए हैं। यहां स्थापित होने वाली मूर्ति के निर्माण और रक्षा की जिम्मेदारी इसी परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी संभालती है। लालबागचा के राजा का पंडाल इतना बड़ा होता है कि यहां हर साल जून महीने से इसकी व्यापक तैयारियां शुरू हो जाती है। विभिन्न पौराणिक ग्रंथों के अनुरूप कई आकृतियां निर्मित की जाती हैं, जिसमें सबसे यूनिक आकृति वाले भगवान गणेश का चयन किया जाता है, अंतिम रूप से स्थापना के लिए। गणेश बाल के राजा के नाम से मशहूर पंडाल की प्रतिमा विशेष तौर पर हल्के झुकाव के साथ आत्मीय मुस्कान से परिपूर्ण होती है। यहां पर भक्तों के दर्शनों के लिए दो लाइनें लगती हैं। एक नवसाची लाइन जिसमें भक्त मंच पर जाकर गणेश की पूजा करते हैं और क्रम से दर्शन पाते हैं। दूसरी लाइन को मुख दर्शनाची लाइन कहते हैं, इस लाइन में सिर्फ दर्शन होते हैं। नवसाची लाइन में दर्शन करने के लिए कभी कभी तो 25 से 40 घंटे तक लग जाते हैं। लालबागचा के राजा भगवान गणेश की जो आकृति यहां प्रतिस्थापित की जाती है, वह एक विशिष्ट आकृति होती है। इस प्रतिमा की सारी रचना परंपरागत गोल मटोल होती है। गौरतलब है कि लालबागचा के राजा की यह विशिष्ट डिजाइन का कॉपी राइट है, ऐसी प्रतिमा शहर ही नहीं, देश का कोई दूसरा पंडाल नहीं बनवा सकता और न ही अपने यहां स्थापित कर सकता है। मुंबई में चूंकि गणेशोत्सव मानसून के दौरान आता है, इसलिए मानसून की बारिश से इस मूर्ति की रक्षा करना चुनौती होती है। लालबागचा के राजा की आध्यात्मिक और सामाजिक उपस्थिति का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि गणेशोत्सव के दौरान यहां के वातावरण में एक खास तरह की आध्यात्मिकता के चुंबकीय आकर्षण को महसूस किया जा सकता है।

प्रकृति की गोद में विलासिता और रोमांस का समन्वय

हर जोड़ा अपनी शादी को खास बनाना चाहता है, और केरल इस सपने को हकीकत में बदलने वाला गंतव्य बन चुका है। चाय बागानों, बैकवाटर्स, समुद्र तटों और हाउसबोट्स के बीच बसी शादियां अब नया ट्रेंड हैं। विदेशी हों या भारतीय, सभी 'गॉड्स ओन कंट्री' की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक भव्यता के बीच यादगार पल रचाना चाहते हैं। जब बर्लिन के जूलियट और पीटर ने अपने विवाह स्थल का निर्णय लिया तो उन्होंने एक ऐसे स्थान की कल्पना की जो इतना एकांत और अनोखा हो ताकि वह उनके एलबम में मधुर स्मृतियों के रूप में सदैव अंकित रहे। उस जोड़े की बारात जब केरल के मुन्नार के जंगल और चाय के बागानों के बेहद करीब स्थित क्वीन विक्टोरिया ब्लॉक से शुरू होकर विला से होते हुए शाही गलियों तक निकला तो देखने वाले देखते रह गए। रथ, और सजे–धजे हाथियों के आगे चल रही थीं केरल की पारंपरिक पोशाक पहने दीपक लिए महिलाएं। जैसे ही बारात ने महल के ब्लॉक में प्रवेश किया, बालकनी से फूलों की वर्षा होने लगी और इटली का एक संगीत बैंड कोरस बजने लगा। पूल के किनारे वाली बालकनी पर पहुंचने पर, झरनों और चाय के बागानों के मनोरम दृश्यों ने दूल्हा–दुल्हन का स्वागत किया। केरल, जिसे 'गॉड्स ओन कंट्री' भी कहा जाता है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य, बैकवाटर्स, हरे–भरे चाय के बागानों, और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। अपने खास मसालों के लिए जाना जाने वाला केरल राज्य अपने खूबसूरत सागर किनारों व हरियाली के सुंदर नजारों की वजह से पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। सफेद रेत और दूर–दूर तक फैला असीम सागर... केरल में घूमने के लिए कई आकर्षक स्थल हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैंकुमुन्नार,

अल्लेप्पी, वायनाड, कोच्चि, थेक्कडी, कुमारकोम, त्रिवेंद्रम... सूची असीमित है। इसकी वजह है कि केरल राज्य के हर कोने में, हर क्षेत्र में प्रकृति ने अपने रंग बिखेरे हुए हैं। साथ ही वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और पहुंचने की सुगमता की वजह से इन दिनों जोड़े वहीं जाकर विवाह करना पसंद कर रहे हैं। केरल में शांत बैकवाटर से लेकर हरी–भरी हरियाली और प्राचीन समुद्र तटों तक, मनमोहक परिदृश्य मौजूद हैं। ये मनोरम दृश्य विवाह समारोहों और फोटोग्राफी के लिए एक शानदार पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं, जो जादुई यादें बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि झिलमिलाते बैकवाटर्स के बीच आयोजित एक प्रीवेडिंग शूट हो या सदियों पुराने किले में एक भव्य रिसेप्शन, जहां विश्वस्तरीय व्यंजनों के साथ–साथ केरल के पारंपरिक भोजन का भी स्वाद मिले तो निस्संदेह यह एक बेहतरीन अनुभव और यादगार विवाह होगा। या फिर पारंपरिक हाउसबोट पर फेरे लेना... शादी के जश्न में विलासिता और रोमांस दोनों का समन्वय किसे अच्छा नहीं लगेगा। कोच्चि हो या कुमारकोम या थेक्कडी या फिर तिरुवनंतपुरम जिले का शंगुमुघम बीच, जहां भारतीय ही नहीं, विदेशी जोड़े भी विवाह बंधन में बंधने के लिए आते हैं। यहां का समुद्र तट अपने विस्मयकारी सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है, जो आकाश में नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों की एक मनमोहक छटा बिखेरता है। जैसे ही सूरज डूबता है, किनारे पर लौटती मछली पकड़ने वाली नावों का दृश्य तटीय दृश्य में एक अनोखा आकर्षण जोड़ देता है जो वहां मौजूद मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर देता है। और जब बात कुमारकोम की आती है तो एक शानदार बैक वाटर वेडिंग का चलन जोर पकड़ रहा है। यहां केरल का पारंपरिक आकर्षण और आधुनिक भव्यता का मिश्रण देखने को मिलता है। कुमारकोम में नारियल के पेड़ों का विस्तार, प्राचीन परिवेश और सुहाना वातावरण, शादियों के लिए एक जादुई माहौल बनाता है। जोड़ों को यहां आकर अंतरंगता और भव्यता दोनों का अहसास होता है। हाउस बोट किराए पर लेकर विवाह उत्सव को और शानदार बनाया जा सकता है। अलेप्पी जिसे 'वेनिस ऑफ द ईस्ट' भी कहा जाता है, एक लोकप्रिय वेडिंग डेस्टिनेशन स्थल की तरह उभर रहा है। वैसे ही वायनाड में विवाह ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। वायनाड एक ऐसा स्थान है, जो शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर, अपनी हरी–भरी हरियाली, धुंध भरी पहाड़ियों और सुहावने मौसम के साथ एक शांत वातावरण प्रदान करता है। यह उन जोड़ों के लिए एकदम सही जगह है जो एक रोमांटिक और मनोरम शादी की पृष्ठभूमि की तलाश में हैं। और मुन्नार तो ऐसा हिल स्टेशन है जो अपने हरे–भरे चाय के बागानों, शांत वातावरण और खूबसूरत दृश्यों के लिए जाना जाता है। विदेशी पर्यटक यहां विशेष तौर पर पारंपरिक रूप से विवाह करने आते हैं। जंगल में बसे किसी रिजॉर्ट में शादी करना उनके अनुभव को यादगार बना देता है।

विपक्ष तो बहाना, 2027 के चुनाव में दबाव बनाना ही असली मकसद, राजभर, पटेल और निषाद ने भाजपा को दिया संदेश

लखनऊ, (संवाददाता)। दिल्ली में हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जिस तरह से पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाले राजग के सहयोगी दलों ने एकजुटता दिखाई है उससे साफ है

कि आगामी चुनावों में भाजपा पर सीटों के बंटवारे का दबाव बढ़ेगा। सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर और अपना दल (एस) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशीष पटेल के तेवरों से साफ हो गया है कि इनकी असली मंशा अखिलेश यादव के पीडीए के तोड़ से ज्यादा अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में भागीदारी बढ़ाने की है। ऐसा नहीं है कि जाति आधारित राजनीति करने वाले नेताओं ने पिछड़ों के हक का मुद्दा पहली बार उठाया है। जातीय दलों के नेता हर बार चुनावी तैयारियों के दौरान इस तरह के मुद्दों को हवा देकर अपना राजनीति लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करते हैं। इससे उन्हें हर सरकार में प्रतिनिधित्व भी मिलता रहा है। ये अलग बात है कि एनडीए में शामिल होने के नाते अपना दल (एस), सुभासपा और निषाद पार्टी के तीनों नेता पिछड़ों की उपेक्षा के लिए विपक्ष को कोस रहे हैं, लेकिन असली निशाना बिहार के विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी में होने वाले आगामी पंचायत व विधानसभा चुनावों में सीटों की हिस्सेदारी पर है। तीनों दलों के नेताओं ने एक स्वर से एकजुटता का दिखावा करते हुए जिस तरह से आरक्षण विरोधियों को सबक सिखाने की चेतावनी दी है, वह अनायास नहीं है। यूपी में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले नवंबर में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी इनकी नजर है। अपना दल (एस) ने अब तक बिहार में चुनाव लड़ने का कोई संकेत नहीं दिया है,

लेकिन सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद तो बिहार चुनाव में सीटों की मांग उठा भी चुके हैं। अधिवेशन में बिहार में निषाद पार्टी के चुनाव लड़ने के एलान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी एकजुटता के पीछे की मंशा आगामी चुनावों में सीटों के बंटवारे की ही है। माना जा रहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को यह संदेश देने के लिए ही अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया।

भव्य फिल्मी रामलीला के सातवें संस्करण के लिए हुआ भूमि पूजन

लखनऊ, (संवाददाता)। रामनगरी एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। रामकथा पार्क में अयोध्या की भव्य फिल्मी रामलीला के सातवें संस्करण के लिए शुक्रवार को भूमि पूजन हुआ। अयोध्या की फिल्मी रामलीला समिति के अध्यक्ष सुभाष मलिक बॉबी और साधु–संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रों के साथ भूमि पूजन हुआ। इस बार रामकथा पार्क में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। 22 सितंबर से दो अक्तूबर तक फिल्मी सितारों से सजी अयोध्या की रामलीला आयोजित होगी। हर रोज शाम सात बजे से रात 10 बजे तक रामलीला चलेगी। खास बात यह है कि इसका सीधा प्रसारण यूट्यूब समेत कई चौनलों पर किया जाएगा। इस बार रामलीला में बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की कई नामी हस्तियां अहम किरदार निभाएंगी। परशुराम के किरदार में मशहूर एक्टर पुनीत इस्सर नजर आएंगे। रजा मुराद अहिरावण के किरदार में होंगे। राजेश पुरी हनुमान जी की भूमिका निभाएंगे। अवतार गिल जनक बनेंगे। राकेश बेदी विभीषण और रावण की भूमिका मनीष शर्मा निभाएंगे। अयोध्या की फिल्मी रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक बॉबी ने बताया कि 28 सितंबर से दिल्ली के कलाकार 190 फीट लंबा रावण का पुतला बनाएंगे। इस बार का रावण दहन ऐतिहासिक होगा। रामलीला में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को शामिल होने के लिए विशेष आमंत्रण भेजा गया है। राम की नगरी अयोध्या में एक बार फिर रामायण जीवंत होगी।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गृहमंत्री को भेजा पत्र, की मांग

लखनऊ, (संवाददाता)। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजा है। इसमें लोकसभा में नेता प्रति पक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। भेजे गए पत्र में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि दो दिन पूर्व दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री के साथ एक व्यक्ति ने हाथापाई की। उनको व्यक्तिगत रूप से चोट पहुंचाने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री के साथ यह घटना उस समय हुई जब वह जन–सुनवाई कर रही थीं। जन–प्रतिनिधि को अपने राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए जन–सामान्य और समर्थकों से संवाद के लिए सदैव उपलब्ध रहना पड़ता है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की व्यक्तिगत सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी कांग्रेस और भारत की राजनीति के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेताओं में से एक हैं। उन्होंने विगत वर्षों में जनता से सीधे संवाद स्थापित करते हुए अनेक कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा और लोक सभा चुनाव प्रचार इत्यादि प्रमुख हैं। वर्तमान समय में राहुल गांधी बिहार में जन–अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें उनके विचारों को सुनने और देखने के लिए लाखों नागरिक जुट रहे हैं। इन परिस्थितियों में उचित होगा कि राहुल गांधी को बिना चूक वाली उच्चतम स्तर की व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की जाए। राहुल गांधी के प्रिय परिजन आतंकी हिंसा का शिकार हुए हैं, जिनमें सुरक्षा चूक एक प्रमुख कारक रही है इसलिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए।।

बीमार छोटी बहन को देखने आई महिला की विषाक्त खिचड़ी खाने से मौत

लखनऊ, (संवाददाता)। रायबरेली जगतपुर के भीख मजरे भवानी बक्स का पुरवा गांव में विषाक्त खिचड़ी खाने के बाद चार लोगों की हालत बिगड़ गई। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं जिला अस्पताल जाते समय रास्ते में एक महिला की मौत हो गई। बृहस्पतिवार की रात भवानी बक्स का पुरवा गांव में राजकुमारी पत्नी पवन कुमार घर पर थीं, उनकी तबीयत खराब थी। इस कारण उधवामऊ ऊंचाहार की रहने वाली उनकी बड़ी बहन बिटाना उनको देखने के लिए घर आई थी। रात करीब 9 बजे खिचड़ी बनाने के लिए कहा गया। इस पर पड़ोस में रहने वाली पूजा पत्नी सुनील कुमार को बुलाया गया और उन्होंने खिचड़ी पकाई। इसके बाद पूजा समेत सभी ने खिचड़ी खाई। कुछ समय बाद पड़ोसी पूजा,

अनुप्रिया, राजकुमारी के बेटे अतुल, राजकुमारी की बड़ी बहन बिटाना की हालत बिगड़ने लगी। इस पर पड़ोसी बीमार लोगों को समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगतपुर पहुंचे। जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर सभी को जिला अस्पताल भेज दिया। पड़ोसी सुनील के अनुसार जिला अस्पताल ले जाते समय जमालपुर के पास बिटाना की मौत हो गई। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बिटाना को मृत घोषित कर दिया। अन्य तीनों का प्राथमिक उपचार शुरू किया। अतुल की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल से एम्स के लिए रेफर कर दिया। एम्स में युवक की हालत बिगड़ते देख डॉक्टरों ने एम्स के भी जवाब दे दिया। युवक का प्राथमिक उपचार इस वक्त सैनिक अस्पताल रायबरेली में चल रहा है। वहीं पूजा और उनकी बेटी अनुप्रिया का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सीएचसी अधीक्षक एलपी सोनकर ने बताया है कि रात लगभग 11रू30 बजे के चार लोग विषाक्त भोजन के कारण गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए गए थे, जिनका प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल भेजा गया था। भोजन में क्या मिला था, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। जांच के बाद ही इस पर कुछ जा सकेगा।

रेलवे पेंशनरों की चिकित्सकीय समस्याएं हों दूर

लखनऊ, (संवाददाता)। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से पेंशनरों व वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बादशाहनगर रेलवे अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ रमेश चंद्र को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। मंडल मंत्री सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान में प्राथमिकता प्रदान की जाए। वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनरों के लिए अलग रजिस्ट्रेशन और दवा काउंटर की सुविधा उपलब्ध हो। डॉक्टर के कमरे के बाहर मरीजों के टोकन नंबर का डिस्प्ले हो। अनुबंधित अस्पतालों व जांच केंद्रों की सूची, अनुबंध अवधि और संबंधित संपर्क व्यक्तियों के मोबाइल नंबर प्रदर्शित किए जाएं। गोमतीनगर के अतिरिक्त आलमबाग, राजाजीपुरम व कानपुर रोड क्षेत्रों में जांच केंद्रों की सुविधा बढ़ाई जाए।

संक्षिप्त खबरें

संविधान संशोधन लोकतंत्र के खिलाफ साजिश, सीबीआई और ईडी हो रहा दुरुपयोग : प्रियंक

लखनऊ, (संवाददाता)। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद और शिवसेना (उद्धव गुट) की वरिष्ठ नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अयोध्या पहुंच कर रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रीराम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में दर्शन कर खुद को सौभाग्यशाली बताया। कहा कि भगवान रामलला की कृपा देश और लोकतंत्र पर बनी रहे। अयोध्या की धरती से प्रियंका चतुर्वेदी ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। कानून संशोधन को लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताया। मोदी सरकार द्वारा संसद में जाए गए संविधान संशोधन विधेयक को उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताया। कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इनका दुरुपयोग हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए किया जा रहा है। एक साल बाद क्लीन चिट दी जाती है। सवाल तो उठेंगे ही। बिहार चुनाव पर भी प्रियंका चतुर्वेदी ने बड़ा दावा किया उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी। जनता सत्ता पक्ष से नाराज है। प्रियंका चतुर्वेदी ने अयोध्या में विकास के साथ रोजगार उपलब्ध कराने की भी मांग रखी।

मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पूर्व सांसद पति से संगठन ने मांगा जवाब

लखनऊ, (संवाददाता)। कानपुर देहात में भाजपा के भीतर अंदरूनी कलह और गुटबाजी खुलकर सामने आई है। इसके बाद महिला कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी और पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज शुक्ला व राजेश तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सभी से सात दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी के निर्देश पर पार्टी के मुख्यालय प्रभारी और महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला की ओर से बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया गया है।

इसमें पार्टी ने तीनों नेताओं की बयानबाजी और गतिविधियों को पार्टी के आचरण के विपरीत माना है। इसे अनुशासनहीनता बताया है। पार्टी नेतृत्व ने यह चेतावनी भी दी है कि तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब न देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 25 जुलाई को भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति अनिल शुक्ला वारसी ने थाने में धरना दिया था। मौजूदा सांसद देवेन्द्र सिंह भोले के गुट के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके जवाब में भोले गुट के माने जाने वाले कानपुर देहात के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज शुक्ला, राजेश तिवारी ने सोमवार को प्रेसवार्ता कर राज्यमंत्री और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए। इस पर बुधवार को मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने भोले पर ब्राह्मण और क्षत्रियों को लड़ाने का आरोप लगाया।

ऐसे तो मिल चुकी ट्रेनों को आउटर पर रोकने से मुक्ति

लखनऊ, (संवाददाता)। ट्रेनों को आउटर पर न रुकना पड़े, इसके लिए दिलकुशा व आलनमगर आउटर को फोरलेन बनाया जा रहा था। लेकिन यह काम ठप सा पड़ गया है। इससे ट्रेनों को आउटर पर रोकने के संकट से फिलहाल मुक्ति मिलते नजर नहीं आ रही है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के चारबाग स्टेशन पर प्रतिदिन 250 से अधिक ट्रेनों की आवाजाही होती है। इससे सवा लाख से ज्यादा पैसेंजर सफर करते हैं। ट्रेनों का ट्रैफिक अधिक होने के चलते दिलकुशा व आलमनगर आउटर पर इन्हें रोकना पड़ता है। इससे यात्रियों को बेवजह दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। औसतन आधे से एक घंटे ट्रेन रुकने से यात्री परेशान होते हैं। यात्रियों की दिक्कतों को दूर करने के लिए रेलवे प्रशासन ने फोरलेन आउटर की योजना बनाई। चारबाग से दिलकुशा के लिए फोरलेन आउटर पर काम भी शुरू किया गया, लेकिन जिस गति से काम किया गया, वह ठप पड़ गई है। इससे यह काम दिसंबर तक भी पूरा होते नजर नहीं आ रहा है। दिलकुशा तक फोरलेन होने के बाद आलमनगर आउटर पर रुकने वाली ट्रेनों की समस्याओं को दूर किया जाना है। चारबाग स्टेशन पर सिग्नलिंग को अपग्रेड करने के लिए रूट रिले इंटरलॉकिंग आरआरआई का कार्य शुरू करवाया गया। यह करीब 40 साल बाद किया जा रहा था। जिसके तहत 250 किमी लंबे पुराने तारों को बदला जाना था। रेलवे प्रशासन ने आरआरआई बिल्डिंग बनवाई, लेकिन आगे के कार्य सुस्त हो गए हैं, जिससे सिग्नलिंग व्यवस्था भी अपग्रेड नहीं हो पाई। चारबाग स्टेशन के अपग्रेडेशन का कार्य पूरे जोर से चल रहा है। फोरलेन आउटर व रूट रिले इंटरलॉकिंग के कार्य को भी गति दी जाएगी।

योगी सरकार की कुनीतियों के खिलाफ कांग्रेस बनाएगी ‘न्याय योद्धा’, अधिवक्ताओं की समस्याओं पर भी खोला मोर्चा

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक प्रेसवार्ता के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि योगी सरकार सच बोलने वालों और सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों पर फर्जी मुकदमे लादकर उन्हें डराने–धमकाने का काम कर रही है। इसमें केवल कांग्रेस कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब अपने विधि विभाग का नए सिरे से पुनर्गठन कर ष्न्याय योद्धाष तैयार करेगी, जो जनता को कानूनी रूप से न्याय दिलाने का काम करेंगे।अजय राय ने कहा कि यह न्याय योद्धा सरकारी तानाशाही का शिकार हो रहे लोगों के साथ खड़े रहेंगे और वोट चोरी व चुनाव आयोग की धांधलियों के खिलाफ जननायक राहुल गांधी के आंदोलन को और मजबूती देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वोटर लिस्ट से नाम काटने जैसी अनियमितताओं को कानूनी स्तर पर चुनौती दी जाएगी और प्रभावित लोगों को पूरी सहायता दी जाएगी।प्रेसवार्ता में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के कोऑर्डिनेटर आसिफ रिजवी रिंकू ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने प्रदेशभर में राजनीतिक प्रतिशोधा की भावना से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगभग 1719 मुकदमे दर्ज कराए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने हर कार्यकर्ता को कानूनी मदद उपलब्ध कराएगी। साथ ही उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया और कहा कि कांग्रेस अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने, जूनियर वकीलों को पाँच साल तक स्टाइपेंड दिलाने और अधिवक्ताओं के लिए बैठने की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कराने की दिशा में संघर्ष करेगी। रिजवी ने यह भी कहा कि योगी सरकार ने अधिवक्ताओं को दस

लाख रुपये का बीमा देने का वादा किया था, लेकिन हमेशा की तरह वह इससे मुकर गई। कांग्रेस इस मुद्दे पर भी दबाव बनाएगी और मृतक अधिवक्ताओं के परिजनों को बीस लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाने की मांग करेगी।विधि विभाग के प्रदेश चेयरमैन नितिन कुमार मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का विधि विभाग हमेशा अधिवक्ता हितों और न्याय की लड़ाई में अग्रणी रहा है और आगे भी इसी संकल्प के साथ संघर्ष जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि न्याय योद्धा के रूप में अधिवक्ता अब पार्टी के आंदोलन को जमीनी स्तर पर धार देंगे।प्रेसवार्ता के दौरान एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया जब कानपुर से अधिवक्ताओं का एक बड़ा समूह कांग्रेस में शामिल हुआ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग कानपुर के चेयरमैन प्रतीक शर्मा के नेतृत्व में मयंक वर्मा, मनीष पोरवाल, रोहन मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, अमित यादव, अजीत अग्निहोत्री, आनंद तिवारी, वैभव शुक्ला, आस्तिक तिवारी, जितेन्द्र कुमार और शिवेन्द्र तिवारी समेत कई अधिवक्ताओं ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सभी अधिवक्ताओं का स्वागत किया और उनके गले में कांग्रेस तिरंगा पट्टिका पहनाकर तथा सदस्यता कार्ड देकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज्वाइनिंग प्रभारी नितिन शर्मा और निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष शरद मिश्रा भी मुख्य रूप से मौजूद रहे।

मानकनगर पुलिस ने 66 किलो अवैध गांजा सहित दो तस्करों को दबोचा

लखनऊ, (संवाददाता)। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के मध्य जोन, थाना मानकनगर की टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से कुल 66.938 किलो अवैध गांजा, दो मोबाइल फोन, दो आधार कार्ड और 3,100 रुपये नकद बरामद हुए हैं।पुलिस उपायुक्त मध्य के निर्देश पर अपर पुलिस उपायुक्त मध्य और सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट के मार्गदर्शन में मानकनगर पुलिस कनौसी फ्लाईओवर की ढलान पर ब्ढै स्कूल के सामने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इसी दौरान दो व्यक्तियोंकृ अनिल कुमार और प्रदीप मोदककृ को रोककर तलाशी ली गई। पूछताछ में उन्होंने अपने पास गांजा होने की बात स्वीकार की।जामा तलाशी के दौरान अनिल कुमार के पास से एक सैमसंग मोबाइल, एक आधार कार्ड, 1,450 रुपये और दो ट्राली बैग तथा एक पिट्ठू बैग में क्रमशः 15.260, 15.270 और 5.320 किलो गांजा बरामद हुआ। वहीं प्रदीप मोदक के पास से एक वीवो मोबाइल, एक आधार कार्ड, 1,650 रुपये और दो ट्राली बैग में 15.310 और 15.210 किलो गांजा मिला।दोनों अभियुक्तों ने बताया कि वे यह गांजा बिहार के न्यू कूच बिहार रेलवे स्टेशन से प्राप्त कर दिल्ली में वसीम नामक व्यक्ति को बेचने का कार्य करते हैं। उन्हें इसमें अच्छा मुनाफा मिलता है और रामदरश नामक व्यक्ति ट्रेन और बस का टिकट उपलब्ध कराता है। आज बस से दिल्ली जाने के लिए इंतजार कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।इस मामले में थाना हाजा पर छक्चै एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और मानवाधिकार आयोग के आदेशों का पूर्ण पालन किया।थाना मानकनगर की इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष अजीत कुमार, उपनिरीक्षक ज्ञानेश्वर सिंह, उपनिरीक्षक मिथिलेश यादव, हेड कांस्टेबल अलाउद्दीन और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस ने कहा कि इस गिरफ्तारी से अवैध मादक पदार्थों की आपूर्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और ऐसे तस्करों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

खाद संकट पर आम आदमी पार्टी का 23 अगस्त को प्रदेशव्यापी धरना–प्रदर्शन

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने इस गंभीर मसले पर शनिवार, 23 अगस्त को प्रदेशभर के सभी तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है।पार्टी के सांसद एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि खेती का मौसम चल रहा है और किसानों को खाद उपलब्ध न कराना सीधा उनकी आजीविका पर प्रहार है। योगी सरकार की लापरवाही ने किसानों की कमर तोड़ दी है।प्रदेश मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे ने कहा कि संजय सिंह के निर्देश पर यह आंदोलन प्रदेश के हर तहसील मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अन्नदाता खाद जैसी बुनियादी सुविधा के लिए दर–दर भटकने को मजबूर हैं, जबकि सरकार बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने में व्यस्त है।दुबे ने बताया कि 23 अगस्त को होने वाले इस विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और किसान शामिल होंगे। पार्टी ने मांग की है कि किसानों को तुरंत पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाए, खाद वितरण में हो रहे भ्रष्टाचार और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई हो तथा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही खेती के मौसम को देखते हुए किसानों को राहत देने के लिए विशेष सहायता पैकेज घोषित करने की भी मांग उठाई गई है।आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि योगी सरकार की प्राथमिकता केवल उद्योगपति हैं, जबकि अन्नदाता की अनदेखी की जा रही है।

'जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे हुई जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति एंव जिला पर्यावरण समिति की बैठक'

'रिपोर्ट—जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' शुक्रवार को जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में वन विभाग से सम्बन्धित जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति एंव जिला पर्यावरण समिति हरदोई की बैठक स्वामी विवेकानन्द सभागार, में आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी, को निर्देश दिये कि जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह के तृतीय शुकवार को ग्राम पंचायत एंव वन विभाग के साथ संयुक्त रुप से ग्राम चौपाल के साथ ग्रीन चौपाल का आयोजन किया जाय। ग्रीन चौपाल का मुख्य उद्देश्य वन एंव वन्य जीव तथा पर्यावरण संरक्षण में जनभागीदारी प्राप्त करना है। वर्ष 2025—26 में जनपद के अन्तर्गत अन्य कार्यदायी विभागों द्वारा कराये गये वृक्षारोपण का अर्न्तविभागीय जाँच समिति द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जाय। रोपित पौधों के सुरक्षा हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जाय। जिसकी कार्ययोजना तैयार कर वन विभाग को शीघ्र प्रेषित की जाय। लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद मुख्यालय से निकलने वाले मुख्य मार्गो पर कराये गये एवन्यू वृक्षारोपण में रोपित पौधों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाय। जिला गंगा समिति, के दौरान जिलाधिकारी द्वारा समस्त कार्यदायी विभागों को जी०डी०पी०एम०एस० पोर्टल पर 10 इन्डीकेटर के अन्तर्गत सूचनाएँ प्रत्येक माह की 10 तारीख के पूर्व प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। सिंचाई विभाग को निर्देश दिये गये कि बाढ़ का पानी कम होते ही पूर्व के बैठको में जनपद के अन्तर्गत क्रमशः तीन घाटो राजघाट, बेरियाघाट एंव तेरापुरसोली पर पक्का घाट निर्माण हेतु भूमि का चिन्हांकन एंव कार्ययोजना तैयार कर आगामी बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाय। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सान्या छावड़ा, जे०बी० शेंडे, प्रभागीय निदेशक सा०वा० वन एंव वन्य जीव प्रभाग, कार्यदायी विभागों के अधिकारियों एवं समस्त अधिशासी अधिकारी, उपस्थित रहें।

प्रदेश स्तरीय सब-जूनियर बालिका हैण्डबाल एवं सब-जूनियर बालक फुटबाल प्रतियोगिता

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर क्रीड़ा अधिकारी ने अवगत कराया है कि खेल निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ के तत्वावधान में खेल विभाग उ0प्र0 एवं उ0प्र0 हैण्डबाल संघ के समन्वय से प्रदेश स्तरीय समन्वय समन्वय सब—जूनियर बालिका हैण्डबाल प्रतियोगिता का आयोजन 01 से 04 सितम्बर 2025 तक बाराबंकी में किया जा रहा है। उक्त के क्रम में जनपद जौनपुर की सब—जूनियर बालिका हैण्डबाल खिलाड़ियों का जनपदीय चयन परीक्षण 23 अगस्त 2025 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से इन्दिरा गांधी स्टेडियम सिद्दीकपुर में किया जायेगा। जनपद स्तर पर चयनित सब—जूनियर बालिका हैण्डबाल खिलाड़ी ही 25 अगस्त 2025 को आयोजित मण्डल स्तरीय चयनध्ट्रायल्स, जो डॉ0 भीमराव अम्बेडकर क्रीड़ा संकुल लालपुर, वाराणसी में प्रातः 8.30 बजे से किया जायेगा, में प्रतिभाग करेंगी। सब—जूनियर बालिका हैण्डबाल खिलाड़ियों की जन्म तिथि 01 जनवरी 2011 या उसके बाद की होनी चाहिए। खेल विभाग उ0प्र0 एवं उ0प्र0 फुटबाल संघ के समन्वय से प्रदेश स्तरीय समन्वय समन्वय सब—जूनियर बालक फुटबाल प्रतियोगिता का आयोजन 31 अगस्त से 07 सितम्बर, 2025 तक पीलीभीत में किया जा रहा है। उक्त के क्रम में जनपद जौनपुर के सब—जूनियर बालक फुटबाल खिलाड़ियों का जनपदीय चयन परीक्षण 25 अगस्त 2025 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से इन्दिरा गांधी स्टेडियम सिद्दीकपुर में किया जायेगा। जनपद स्तर पर चयनित सब—जूनियर बालक फुटबाल खिलाड़ी ही 29 अगस्त 2025 को आयोजित मण्डल स्तरीय चयनध्ट्रायल्स, जो डॉ0 सम्पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा, वाराणसी में अपरान्ह 2.00 बजे से किया जायेगा, में प्रतिभाग करेंगे। सब—जूनियर बालक फुटबाल खिलाड़ियों की जन्म तिथि 01 जनवरी 2012 या उसके बाद तथा 31 दिसम्बर, 2013 तक या उसके पूर्व का होना चाहिए। मण्डल स्तरीय चयनध्ट्रायल्स उपरान्त मण्डल की टीम का गठन किया जायेगा, मण्डल स्तरीय टीम ही प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित प्रारूप पर अपना पात्रता प्रमाण पत्र फोटो सहित तथा आयु प्रमाण—पत्र प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित तथा आधार कार्ड के साथ हाई स्कूल अंक पत्र की छायाप्रति साथ लेकर जनपदीय चयनध्परीक्षण में प्रतिभाग कर सकते हैं।

'परीक्षा से पूर्व सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाएं— संतोष कुमार सचान'

'रिपोर्ट—जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' 06 एवं 07 सिम्बर 2025 को जनपद में होने वाली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2025 की होने वाली च्म्ज परीक्षा तैयारी के संबंधा में स्थानीय पीडब्लूडी गेस्ट हाउस में माननीय सदस्य आयोग संतोष कुमार सचान ने च्म्ज परीक्षा की तैयारी के संबंध में जनपद के अधिकारियों से समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा की परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने हेतु परीक्षा से पूर्व सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाएं और परीक्षा की

निगरानी के लिए जनपद स्तर पर एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाये। परीक्षा वाले दिनों में आने वाले अभ्यर्थियों को कोई परेशानी न हो इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा परीक्षा केन्द्रों एवं भीड़—भाड़ वाले चौराहों पर यातायात व्यवस्था ठीक बनाये रखा जायें। समीक्षा बैठक में वरिष्ठ कोषाधिकारी, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रफुल्ल त्रिपाठी,अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी एम0पी0 सिंह ,जिला विद्यालय निरीक्षक बालमुकुन्द प्रसाद आदि उपस्थित रहे।

मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामीण चौपाल में किया प्रतिभाग

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना)

आज मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा द्वारा ग्राम पंचायत सचिवालय परिसर में आयोजित ग्रामीण चौपाल महितापुर ब्लाक साण्डी में प्रतिभाग किया गया। ग्रामीण चौपाल में ग्राम्य विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, पशुपालन विभाग, पंचायत राजी विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, खाद्य रसद विभाग, चिकित्सा विभाग, आयुष्मान कार्ड जारी करने हेतु कैम्प लगाये गये, विभिन्न स्टालों पर कुल 55 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 2छ9 आवेदन पत्रों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। चौपाल में कुल 04 विधवा पेंशन के लाभार्थियों की ई के0वाई0सी0 की करायी गयी, 04 ब्लड सैम्पल लेकर उन्हें मोके पर ही रिपोर्ट दी गयी, 21 आयुष्मान कार्ड निर्गत किए गए। इसके साथ ही 06 नवीन शौचालय एवं 12 राशन कार्ड ऑन लाईन कराये गये। ग्रामीण चौपाल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न निशुल्क दवाओं का वितरण किया गया तथा विभिन्न विभागों द्वारा अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गयी। ग्रामीण चौपाल में लोगों द्वारा शौचालय,पेंशन एवं राशन कार्ड की मांग की गयी। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी साण्डी को निर्देशित किया गया है कि यदि कोई पात्र लाभार्थी छूट जाता है तो अगले दिन कैम्प लगाकर उन्हें लाभान्वित कराया जाये। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा नवजात शिशु सारा खान पुत्री जीसान का अन्नप्रासन कराया गया तथा कल्पना पत्नी संजीव कुमार की गोदभराई करायी गयी। ग्रामीण चौपाल में डा0 ए0 के0 सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डा0 अखिलेश बाजपेई, एम0ओ0आई0सी0, साण्डी, महेश चन्द्र, खण्ड विकास अधिकारी, साण्डी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, साण्डी के साथ राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, खाद्य रसद विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के ब्लाक स्तरीय अधिकारीध्कर्मचारी उपस्थित रहे।

01 जुलाई से 30 सितम्बर तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जाएगा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीयध्सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं अनिल कुमार वर्मा—प्रथम, माननीय जनपद न्यायाधीशध अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर के तत्वावधान में दिनांक 01 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किया जायेगा। इस मध्यस्थता अभियान में वैवाहिक विवाद के मामलें, दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चौक बाउन्स के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, सेवा विवाद के मामले, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले, ऋण वसूली के मामले, सम्पत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले, बेदखली से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, अन्य उपयुक्त दीवानी मामले आपसी सुलह—समझौतें के आधार पर निस्तारित किये जायेगें। अतः वादकारी गण एवं अधिवक्ता गण अपने—अपने वादों से सम्बन्धित न्यायालयों में सम्पर्क स्थापित कर वादों को मध्यस्थता हेतु सुलह—समझौता केन्द्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर में संदर्भित करायें एवं अधिकतम वादों का निस्तारण कराकर उक्त अभियान का लाभ उठायें।

स्कूली ड्रेस व अनुशासन मे रहने वाले बच्चों की फोटो दिखेगी सभी प्राइमरी स्कूलों के मुख्य द्वार पर

अयोध्या ।प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल में अधिक से अधिक बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार एक से बढ़कर एक महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है ।अब प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के सामने फ्लेक्स बोर्ड तथा बैनर पर उन बच्चों की तस्वीरे लगाई जाएगी जो की साल भर स्कूल के ड्रेस,अच्छे अंको से उत्तीर्ण व अनुशासन में रहे हो ।इस बात की जानकारी बीएसए अवनीश कुमार पांडे ने दिया ।बताया कि यह आदेश अभी कुछ दिनों पूर्व ही बीएसए कार्यालय को मिला है ।उन्होंने बताया कि यह सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुत ही अच्छी योजना है ।इससे प्राइमरी व जूनियर स्कूलों मे पढने वाले बच्चों को स्कूलों के भेष भूषा में आने तथा साथ—साथ पढ़ाई करने और अनुशासन बनाए रखने में प्रेरणादायक साबित होगी ।बताया कि शीघ्र ही इस आदेश को सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा ।इसके लिए बीच—बीच में सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों तथा अध्यापकों के साथ—साथ खंड शिक्षा अधिकारी को भी इस पर निगरानी करने के लिए निर्देश भी दिया जाएगा। बताया कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि प्राय यह देखने में आ रहा था कि इन सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे गंदे व अन्य वेशभूषा पहन कर सीधे स्कूल आ जाते थे वहीं अनुशासन व पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था ।अगर अब बच्चों की फोटो स्कूल के सामने बैनर व पोस्ट पर देखेंगे तो और और स्कूली छात्रों के अंदर भी अनुशासन के साथ—साथ पढ़ाई व स्कूल के परिधान में आने का प्रोत्साहन जागेगा ।बताया कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों को अच्छी सी अच्छी शिक्षा देने के लिए कुछ विद्यालयों में कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है।

पक्षियों की मौत और बीमारी पर विशेष निगाह रखें

भदोही, (संवाददाता)। बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को देखते हुए जिले में एहतियाती कदम तेज कर दिए गए हैं। बृहस्पतिवार को विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में पशुपालन, पंचायत राज, नगर पंचायत, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन, वन एवं पर्यावरण, सिंचाई, परिवहन, लोक निर्माण और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. एके सिंह ने बर्ड फ्लू की प्रवृत्ति, इसके प्रभाव और बचाव के उपायों की जानकारी दी। सीडीओ ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि कुक्कुट और उनके उत्पाद के परिवहन पर रोक लगाने के साथ जैव सुरक्षा ।

कांति नगर कालोनी मे भी मना धूमधाम से मना छठ, हुआ भंडारे का आयोजन

अयोध्या। गुरुवार को शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्रमुख मंदिरों तथा कई लोगों ने अपने—अपने घरों पर धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण की छठ मनाया ।कोतवाली नगर क्षेत्र के नाका स्थित कांति नगर कॉलोनी निवासी राम बहादुर यादव कोटेदार के यहां भगवान श्री कृष्ण का छठ पूजा हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया ।इस मौके पर मोहल्ले की महिलाओं तथा बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक भगवान श्री कृष्णा के भजनों को गाकर आसपास की वातावरण को भक्तिमय कर दिया वहीं छोटे—छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने कान्हा – राधा के रूप में एक से बढकर एक आकर्षण नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम मे चार चाँद लगा दिया ।इस मौके कार्यक्रम में जसुमत मैया से पूछे नंदलाला, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,हाथी घोडा पालकी जय कन्हैया लाल की,मैया मौरी मै नहि माखन खायो जैसे एक से बढ़कर एक आकर्षक गानों पर छोटे—छोटे बच्चों ने नृत्य किया ।इस मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गयाजहाँ देर रात तक आसपास के श्रद्धालुओं ने आकर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर अभिषेक यादव के अलावा कॉलोनी के काफी संख्या में महिलाओं व बच्चों ने भाग लिया।

सरयू में समाए दो गांव, बहे मकान

सीतापुर, (संवाददाता)। करीब 20 बीघा कृषि योग्य भूमि कटान की भेंट चढ़ गई है। लहरों के निशाने पर अब लोधपुरवा व सुन्दरपुरवा गांव भी हैं। सामान समेटकर लोग सुरक्षित स्थान पर शरण ले रहे हैं। वहीं, तीनों बैराजों से बृहस्पतिवार को 4.37 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बृहस्पतिवार को सरयू नदी के जलस्तर में 10 सेमी की कमी आई है। जलस्तर अब 118.10 मीटर पर है। खतरे के निशान 119 मीटर से पानी 90 सेमी नीचे बह रहा है। जलस्तर घटने से कटान लगातार तेज हो रहा है। बुधवार को शुकुलपुरवा के मजरा खुन्नापुरवा व रामरुपपुरवा व लोधनपुरवा के 24 घर कटान में बह गए थे। इनमें खुन्नापुरवा के 19 घर, रामरुपपुरवा के चार तथा लोधनपुरवा का एक घर शामिल था। बृहस्पतिवार को रामरुपपुरवा का एक घर कटने के साथ इसका और खुन्नापुरवा का अस्तित्व खत्म हो गया। अब लहरों के निशाने पर लोधनपुरवा और सुंदरपुरवा हैं। लोधपुरवा में शेष बचे करीब सात घरों की ओर लहरें कटान करते हुए बढ़ रही हैं। सरयू की धारा तेजी से कटान करती हुई फसल समेत खेतों को निगलती जा रही है। कंपोजिट स्कूल का एक कमरा नदी की धारा में समाने के बाद अवशेष भवन का कटान नदी तेजी से कर रही है। सुंदरपुरवा के पास भी नदी तेजी से कटान कर आबादी के नजदीक पहुंच रही है। पिछले 24 घंटों में करीब 20 बीघे जमीन नदी में समा गई है। कटान से लोग सहमे हुए हैं और गृहस्थी समेटकर सुरक्षित ठिकाने की ओर जा रहे हैं।

सरयू में समाए दो गांव, बहे मकान

सीतापुर, (संवाददाता)। करीब 20 बीघा कृषि योग्य भूमि कटान की भेंट चढ़ गई है। लहरों के निशाने पर अब लोधपुरवा व सुन्दरपुरवा गांव भी हैं। सामान समेटकर लोग सुरक्षित स्थान पर शरण ले रहे हैं। वहीं, तीनों बैराजों से बृहस्पतिवार को 4.37 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बृहस्पतिवार को सरयू नदी के जलस्तर में 10 सेमी की कमी आई है। जलस्तर अब 118.10 मीटर पर है। खतरे के निशान 119 मीटर से पानी 90 सेमी नीचे बह रहा है। जलस्तर घटने से कटान लगातार तेज हो रहा है। बुधवार को शुकुलपुरवा के मजरा खुन्नापुरवा व रामरुपपुरवा व लोधनपुरवा के 24 घर कटान में बह गए थे। इनमें खुन्नापुरवा के 19 घर, रामरुपपुरवा के चार तथा लोधनपुरवा का एक घर शामिल था। बृहस्पतिवार को रामरुपपुरवा का एक घर कटने के साथ इसका और खुन्नापुरवा का अस्तित्व खत्म हो गया। अब लहरों के निशाने पर लोधनपुरवा और सुंदरपुरवा हैं। लोधपुरवा में शेष बचे करीब सात घरों की ओर लहरें कटान करते हुए बढ़ रही हैं। सरयू की धारा तेजी से कटान करती हुई फसल समेत खेतों को निगलती जा रही है। कंपोजिट स्कूल का एक कमरा नदी की धारा में समाने के बाद अवशेष भवन का कटान नदी तेजी से कर रही है। सुंदरपुरवा के पास भी नदी तेजी से कटान कर आबादी के नजदीक पहुंच रही है। पिछले 24 घंटों में करीब 20 बीघे जमीन नदी में समा गई है। कटान से लोग सहमे हुए हैं और गृहस्थी समेटकर सुरक्षित ठिकाने की ओर जा रहे हैं।

बिना डॉक्टर के संचालित अभय सिंह मेमोरियल अल्ट्रासाउंड सेंटर सील

भदोही, (संवाददाता)। नगर स्थित अभय सिंह मेमोरियल अल्ट्रासाउंड सेंटर बृहस्पतिवार को सील कर दिया गया। ज्ञानपुर एसडीएम भान सिंह व सीएचसी अधीक्षक आशुतोष पांडेय ने जांच पड़ताल के बाद सेंटर को सील किया। जांच के दौरान संज्ञान में आया कि बिना डॉक्टर के ही 72 अल्ट्रासाउंड किया गया। अवैधा रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड को लेकर डीएम शैलेष कुमार सख्त है। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जांच टीम ने अल्ट्रासाउंड के पंजीकृत डॉ. आरके मौर्या को फोन किया। वे वाराणसी में थे। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि वहां न हम कभी आते थे और न कभी आएंगे। इतने में फोन काट दिया। एसडीएम ने सेंटर को सील कर दिया। गोपीगंज में बीते 15 दिनों में तीन अल्ट्रासाउंट सेंटर पर गाज गिर चुकी है। पिछले सप्ताह अनुराग डायग्नोस्टिक सेंटर, कुबेर डायग्नोस्टिक सेंटर को सील किया गया था। ज्ञानपुर में सिद्ध विनायक अल्ट्रासाउंड सेंटर भी सील किया गया है। इसके बाद अब अभय सिंह मेमोरियाल अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील हुआ है। जांच टीम ने मौके पर देखा कि बिना डॉक्टर के ही मरीजों का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। कुल 72 मरीजों का अल्ट्रासाउंड किया गया था। सीएचसी अधीक्षक डॉ. आशुतोष पांडेय ने बताया कि शिकायत के बाद जांच की गई। चिकित्सक के न मिलने पर सील कर दिया गया है।

सीतापुर को जल्द मिलेगा बस स्टेशन : दयाशंकर

सीतापुर, (संवाददाता)। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि सीतापुर को जल्द एक नया बस स्टेशन मिलेगा। इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार परिवहन निगम की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। परिवहन मंत्री बतौर मुख्य अतिथि बृहस्पतिवार को श्री चंद्र प्रकाश पुरी कल्याण सेवा समिति की ओर से आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। नगर पालिका के निकट एक मैरिज लान में आयोजित सम्मान समारोह में परिवहन मंत्री ने कहा कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सभी व्यक्तियों को समाज में जन कल्याण के लिए काम करने चाहिए। समिति की ओर से 11 दिव्यांगों को ट्राई साइकिल देना व किसानों का सम्मान करना प्रेरणादायक है।

कटान से कंपोजिट स्कूल व 24 घर सरयू में समाए

सीतापुर, (संवाददाता)। सरयू के जलस्तर में बुधवार को 10 सेमी कमी आने से कटान तेज हो गई है। बेकाबू लहरों की जद में आकर शुकुलपुरवा कंपोजिट विद्यालय के भवन का एक कमरा सरयू में समा गया। कटान इसी तरह होता रहा तो स्कूल का शेष भवन भी नदी में समा सकता है। इसके अलावा करीब 24 घर व 25 बीघा कृषि योग्य भूमि कटान की भेंट चढ़ गई। बेघर परिवार गृहस्थी लेकर नाव से सुरक्षित ठिकाने की ओर पलायन कर रहे हैं। सेवता विधायक व महमूदाबाद तहसीलदार ने बुधवार को कटान वाले स्थान पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उधर, तीनों बैराजों से बुधवार को 4.04 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सरयू नदी का जलस्तर बुधवार को 118.20 मीटर दर्ज किया गया। मंगलवार की तुलना में पानी 10 सेमी घटा है। पानी घटने के साथ कटान तेज हो गई है। शुकुलपुरवा के मजरा खुन्नापुरवा में करीब 10 वर्ष पहले पांच कमरों वाले परिषदीय कंपोजिट स्कूल भवन का निर्माण कराया गया था। इस विद्यालय में करीब 246 बच्चे पंजीकृत हैं। कटान करती सरयू की लहरों ने बुधवार दोपहर इस विद्यालय को चपेट में ले लिया। स्कूल का एक कमरा कटकर नदी में बह गया। शेष चार कमरे भी काटन की जद में हैं। चार दिन पहले ही शिक्षकों ने यह स्कूल भवन खाली कर दिया था। विद्यालय में पंजीकृत बच्चों में से कुछ को पड़ोस के प्राथमिक विद्यालय कोठार व कुछ बच्चों को शुकुलपुरवा के पंचायत भवन में पढ़ाया जा रहा है। विद्यालय का सामान भी अन्य

जगह स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा कुन्नापुरवा, रामरूपपुरवा और लोधनपुरवा के कृपाराम, संकटा, अमृतलाल, रामवती, आरती, परसराम समेत करीब 24 लोगों के घर नदी की धारा में समाहित हो गए हैं। कटान करती सरयू लगभग 25 बीघा खेत भी फसल समेत निगल गई। कटान की तेजी और लगातार होने वाली तबाही देख शुकुलपुरवा के ग्रामीण दहशत में हैं। गृहस्थी समेटकर लोग नाव से सुरक्षित ठिकाने की ओर पलायन कर रहे हैं।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार—पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।